www.sanjanabharati.com
दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित
facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 नये आर्थिक सूरज बनने के सुखद एवं...
3 चेयरमैन फात्मा रजा के अच्छे कार्य करने वाले...
4 करनाल के विधायक जगमोहन आनंद ने की...

वर्ष: 9 | अंक: 213 | दिल्ली, बुधवार, 28 मई 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

सांबा सेक्टर में एक पोस्ट का 'सिंदूर' रखा जाएगा नाम!

जम्मू-कश्मीर (एजेन्सी)। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के बाद सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने 10 मई को पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलाबारी के दौरान शहीद हुए जवानों के नाम पर सांबा सेक्टर में एक पोस्ट का नाम सिंदूर रखने और दो अन्य का नाम रखने का प्रस्ताव रखा है। इस मुद्दे पर बोलते हुए बीएसएफ के आईजी जम्मू फ्रंटियर शशांक आनंद ने कहा कि सीमा पार से की गई गोलाबारी से लड़ते हुए भारतीय सेना के एक नायक समेत तीन जवान शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने हमारी चौकियों को निशाना बनाने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन भेजे। बीएसएफ इन ड्रोनों से सक्रिय रूप से निपट रहा था। हालांकि, ऐसी ही एक घटना के दौरान एक दुखद घटना घटी जब बीएसएफ के सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, कांस्टेबल दीपक कुमार और भारतीय सेना के नायक सुनील कुमार एक ड्रोन का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे; ड्रोन ने एक पेलोड गिरा दिया, जिसके परिणामस्वरूप तीनों की मौत हो गई। आईजी शशांक आनंद ने कहा कि हम अपने दो पोस्ट का नाम अपने शहीद जवानों के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखते हैं और सांबा सेक्टर में एक पोस्ट का नाम 'सिंदूर' रखने का प्रस्ताव रखते हैं।

केरल में भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित

केरल (एजेन्सी)। केरल में पहले से ही भारी बारिश हो रही है, ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने केरल के कई जिलों के लिए लाल, नारंगी और पीले अलर्ट जारी किए हैं, जिसमें भारी से लेकर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। केरल में लगातार हो रही बारिश के कारण मंगलवार को जनजीवन प्रभावित रहा। राज्य में कई जगहों पर ट्रेनें देरी से चल रही हैं, निचले इलाकों में जलजमाव हो गया है और कस्बों एवं गांवों में यातायात बाधित हो रहा है। उत्तरी जिलों में पेड़ों के रेलवे लाइन पर गिरने के कारण कल रात से ही स्थिति चिंताजनक है। अधिकारियों ने बताया कि कोझिकोड-आरीकोड मार्ग पर एक विशाल पेड़ उखड़ने की वजह से टूटा बिजली का तार रेलवे लाइन पर गिर गया। अधिकारियों को रेलवे लाइन से तार को हटाने और मार्ग पर ट्रेन का सामान्य यातायात बहाल करने में कुछ घंटे लगे। रेलवे सूत्रों के अनुसार तिरुवनंतपुरम जाने वाली वंदे भारत और परशुराम एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं।

पहलगाम में उमर अब्दुल्ला ने की कैबिनेट मीटिंग

जम्मू-कश्मीर (एजेन्सी)। जम्मू-कश्मीर में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर सरकार ने पहलगाम में विशेष कैबिनेट बैठक की। यह पहली बार है जब इस सरकार के कार्यकाल में पारंपरिक ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर या शीतकालीन राजधानी जम्मू के बाहर कैबिनेट बैठक हो रही है। विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित करने का निर्णय अब्दुल्ला द्वारा शनिवार को पहलगाम आतंकी हमले से बुरी तरह प्रभावित जम्मू-कश्मीर पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए दोहरे दृष्टिकोण का प्रस्ताव देने के दो दिन बाद आया है। उन्होंने केंद्र से सार्वजनिक उपक्रमों को कश्मीर में बैठकें आयोजित करने और संसदीय समिति की बैठकें वहां आयोजित करने का आदेश देने का आग्रह किया। हालांकि बैठक का विशिष्ट एजेंडा अभी तक गुप्त रखा गया है, लेकिन अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि इसका प्राथमिक महत्व राष्ट्र-विरोधी और असामाजिक तत्वों को यह प्रतीकात्मक संदेश देना है कि जम्मू-कश्मीर में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।

हमारी सरकार ने भारत से आतंकवाद का नाश करने का फैसला किया है: प्रधानमंत्री मोदी

(एजेन्सी)।

गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के गांधीनगर में पाकिस्तान पर फिर हमला बोला और कहा कि उनकी सरकार ने भारत से आतंकवाद का नाश करने का फैसला किया है। उन्होंने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 5,536 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। मैं पिछले दो दिनों से गुजरात में हूँ। कल मैंने वडोदरा, दाहोद, भुज और अहमदाबाद का दौरा किया और आज सुबह गांधीनगर गया। जहाँ भी गया, वहाँ देशभक्ति की लहर सी महसूस हुई, केसर के समुद्र की गर्जना जैसी। केसर के समुद्र की गर्जना, लहराता तिरंगा और हर दिल में मातृभूमि के लिए अपार प्रेम। यह नजारा देखने लायक था, यह एक अविस्मरणीय दृश्य था।

सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर 1947 में हमने कश्मीर में घुसने वाले मुजाहिद्दीनों को मार गिराया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। पीएम मोदी ने कहा, "जब 1947 में बंटवारा हुआ तो उस समय जंजीरें काट देनी चाहिए थीं, लेकिन इसके बजाय देश तीन हिस्सों में बंट गया। इसके तुरंत बाद कश्मीर में पहला आतंकी हमला हुआ और पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। अगर हमने इन मुजाहिद्दीनों को मार गिराया होता, अगर हमने सरदार पटेल की बात मानी होती, तो वे चाहते थे कि सेना तब तक न रुके जब तक हम पीओके वापस न ले लें। 75 साल तक हमने कष्ट झेले और पहलगाम में जो हुआ, वह उसी हमले का विकृत रूप था। भारतीय सेना ने हर बार पाकिस्तान को हराया है। पाकिस्तान समझ गया है कि वह भारत से नहीं जीत सकता।

पीएम मोदी ने सीमा पार आतंकवाद का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद कोई छद्म युद्ध नहीं है, यह आपकी युद्ध रणनीति है। आप हम पर युद्ध कर रहे हैं।

आतंकवाद कोई छद्म युद्ध नहीं है, यह आपकी युद्ध रणनीति है-प्रधानमंत्री

यह कहते हुए उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि पर बहुत खराब तरीके से बातचीत की गई और इसमें कश्मीर में बांधों से गाद निकालने तक की अनुमति नहीं थी।

पीएम मोदी ने कहा कि 26 मई 2014 को मैंने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम अब जापान से आगे निकल गए हैं। मुझे आज भी पूरे देश में वह उत्साह याद है जब हम छठे से पांचवें स्थान पर पहुंचे थे, खासकर तब जब भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया था, उसी देश ने हम पर 250 साल तक राज किया था।

सीएम रेखा गुप्ता ने 1984 सिख हिंसा पीड़ितों के परिजनों को दी सरकारी नौकरियों की नियुक्ति-पत्र

प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद सिख दंगों के पीड़ितों को मिला न्याय-सिरसा

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय परिसर में 1984 के सिख दंगो के पीड़ित परिवारों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस कार्यक्रम में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित पीड़ित परिवारों के सदस्य उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने आधिकारिक नियुक्ति पत्र सौंपकर न केवल नौकरियाँ दी हैं, बल्कि उन हजारों परिवारों की गरिमा और पहचान को भी मान्यता दी है, जो इतने वर्षों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे।1984 के सिख-विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में यह कदम मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगो को सम्बोधित करते हुए कहा कि 1984 के दंगे भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे भुलाना बहुत ही मुश्किल है। इन दंगो में जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनके दर्द की कोई भरपाई नहीं हो सकती। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र की सत्ता में आने के बाद 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने और आरोपियों को सजा दिलाने का काम शुरू किया। उन्ही के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार इन पीड़ित परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने हेतु आज इन्हे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, यह न्याय है, जो चालीस वर्षों की चुप्पी और संघर्ष के बाद इनके जीवन में चला आया है। हम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन इनका वर्तमान जरूर बेहतर कर सकते है। उन्होंने आगे कहा कि इन चार दशकों में हिंसा पीड़ितों ने असहनीय कष्ट सहे, परंतु दुर्भाग्यवश कोई भी पूर्व सरकार न उनके दर्द को समझ सकी और न ही उन्हें कोई ठोस मदद दे सकी। आज जब हम 125 परिवारों को नियुक्तियाँ देने में सक्षम हुए हैं, और उनमें से 19 लोग अपनी सेवाएं शुरू कर रहे है, तो यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों की बहाली का प्रतीक है। कैबिनेट मंत्री श्री मंजींदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह क्षण मेरे लिए बेहद व्यक्तिगत है-न केवल एक मंत्री के रूप में, बल्कि एक ऐसे सिख परिवार के सदस्य के रूप में जिसने यह इंतजार, यह पीड़ा, यह उम्मीदें देखी हैं। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि यह सरकार आखिरकार वह दे पाई है जो उन्हें वर्षों पहले मिलना चाहिए था।

यह ऐतिहासिक निर्णय उन पूर्ववर्ती सरकारों की संवेदनहीनता पर एक करारा जवाब भी है, जिन्होंने बार-बार अपीलों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने आगे कहा कि यह नियुक्ति अपने आप में ऐतिहासिक है क्योकि नौकरी से सम्बंधित पात्रता पर दिल्ली सरकार ने छूट दी है। इस प्रक्रिया से यह पूर्णतः साबित होता है कि न्याय में देर जरूर होती है, लेकिन हर बार वह नकारा नहीं जा सकता, हम गरिमा के साथ पीड़ितों के साथ है।

पिछली सरकार जो कार्य 10 साल में पूरा नहीं कर पाई, वह हमारी सरकार ने 100 दिन में पूरा करके दिखाया है। और उन्होंने 1984 के आरोपियों को बचाने का काम किया जबकि रेखा सरकार ने उनके पीड़ितों को नियुक्ति पत्र देने का कार्य किया है।

सीएम नायब सिंह सैनी ने की बड़ी घोषणाएं

दुर्घटना में मृत्यु होने पर आयुष योग सहायकों के परिवारों को 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करने वाले आयुष योग सहायकों की सेवा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को अपने ऐच्छिक कोष से तीन-तीन लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। इसके अलावा, उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब योग व प्राकृतिक चिकित्सकों का भी पंजीकरण किया जाएगा, इसकी इसी वर्ष से शुरूआत की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा तक योग को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया हुआ है। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए योग, खेल व अन्य विषयों को सम्मिलित करते हुए पाठ्यक्रम में शामिल कर औपचारिक रूप से इनकी परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। इससे बच्चों को बचपन से ही योग को समझने और जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं पंचकूला में आयोजित भव्य योग महोत्सव के दौरान की। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से 'सूर्य नमस्कार अभियान 2025' के 264 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इस मौके पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुष मंत्री कुमारी आरती सिंह राव भी उपस्थित रहीं।

मुख्यमंत्री ने विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल, स्वस्थ और सफल भविष्य की कामना की और कहा कि यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा की मिट्टी में प्रतिभा और परिश्रम की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार अभियान 2025 में योग संस्थानों, आयुष योग सहायकों, शैक्षणिक संस्थाओं, जेल विभाग, पुलिस, सेना और अर्ध सैनिक बलों की भागीदारी रही, जो हमारे लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आयुष विभाग में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए 3 पोर्टल-ई-मार्केट प्लेस पोर्टल, आयुष औषधि इन्वेंटरी पोर्टल और ई औषधि लाइसेंसिंग पोर्टल भी लॉन्च किये। इनमें ई-मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से औषधीय पौधे तैयार करने वाले किसान, स्टाकिट्स आदि अपना पंजीकरण कर सकेंगे। उनसे कोई भी व्यक्ति औषधीय पौधों की खरीद कर सकेगा।

आयुष औषधियों की प्रबंधन प्रणाली पर आयुष विभाग के अधिकारी औषधियों की मांग कर सकते हैं और स्टॉक अपडेट देख सकते हैं। इसके अलावा, लाइसेंसिंग पोर्टल पर नये अथवा लोन लाइसेंस प्राप्त करने, पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण आदि के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का यह योग महोत्सव एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह आगामी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2025 से ठीक 25 दिन पहले आयोजित किया जा रहा है। ऐसे 264 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुए 'सूर्य नमस्कार 2025' अभियान में अपने असाधारण प्रदर्शन से हम सभी को गौरवान्वित किया है।

उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार अभियान स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी से आरम्भ हुआ था और महर्षि दयानद सरस्वती जी की जयंती 12 फरवरी को इसका समापन हुआ। इसमें 46 लाख लोगों ने भागीदारी की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का खेलो इंडिया अभियान बना खिलाड़ियों के लिए वरदानः रविन्द्र इन्द्राज

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। समाज कल्याण, एससी/एसटी कल्याण, चुनाव और सहकारिता मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने मंगलवार को तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित दिल्ली गेम्स 2025 के समापन समारोह का बतौर विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद अरुण सिंह के साथ शुभारंभ किया।

समाज कल्याण मंत्री ने इस अवसर पर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में खेलों के बजट में तीन गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा खेल अवसंरचना के विकास और आधुनिक सुविधाओं के निर्माण में निवेश किया गया है। 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम के तहत देशभर में 1,000 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं। यह योजना जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उनके लिए वरदान बन गई है। खेलो इंडिया से पारंपरिक खेलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अब भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए प्रयासरत है। श्री रविन्द्र इन्द्राज ने कहा की दिल्ली गेम्स 2025 ने राजधानी में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस आयोजन ने दिल्ली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। इस अवसर पर विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी शामिल थीं, जो दिल्ली की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती हैं।

भगवंत मान ने मोहाली के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय का किया औचक निरीक्षण

संजना भारती संवाददाता

साहिबजादा अजीत सिंह नगर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक दौरा करके नई लागू की गई 'ईजी (आसान) रजिस्ट्रेशन योजना' की प्रगति का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस दौरे का उद्देश्य अधिकारियों में कमियाँ ढूंढना नहीं था, बल्कि सरकारी कार्यालयों में प्रक्रियाओं को और अधिक सुचारू बनाना है। उन्होंने कहा कि शायद यह पहली बार होगा जब पंजाब के लोगों ने किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से सरकारी दफ्तरों का दौरा करते देखा होगा। भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि इस दौरे का उद्देश्य नागरिक-केन्द्रित सेवाओं को कुशल और पारदर्शी ढंग से प्रदान करके जनता की भलाई सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दौरा इस महत्वपूर्ण परियोजना की प्रगति की समीक्षा के उद्देश्य से था, जिसका लक्ष्य लोगों के लिए संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने कहा कि वह इस परियोजना के परिणामों का स्वयं मूल्यांकन कर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के कार्यों की समीक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने इस पहल को देशभर में अपनी तरह की पहली पहल बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण को सुचारू और परेशानी रहित बनाना है। योजना के फायदों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए निजी डीड राइटरों (वसीका नवीसों) पर निर्भरता को कम करती है और नागरिकों को अपने लेन-देन का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करने की सुविधा देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को अब फीस भुगतान के लिए बैंकों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन भुगतान प्रणाली सभी आवश्यक फीस-स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क सहित-को एकल डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से अदा करने में मदद करती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह योजना सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिमांड ड्राफ्ट या नकद भुगतान की आवश्यकता को समाप्त करती है। इस योजना की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 48 घंटे के भीतर रजिस्ट्री दस्तावेजों की पूर्व-पड़ताल प्रक्रिया और अपॉइंटमेंट आधारित रजिस्ट्रेशन प्रणाली नागरिकों के लिए परेशानी को कम करते हुए पूरी प्रक्रिया को सुगम बनाती है। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से पैसों की बचत के साथ-साथ कार्य-कुशलता में भी सुधार होता है। भगवंत सिंह मान ने यह भी बताया कि ऑनलाइन पोर्टल पर पहले से निर्धारित सरकारी दरों और "कैलकुलेट माय फीस" टूल की सुविधा उपलब्ध है, जो नागरिकों को अपने खर्चों का बेहतर प्रबंधन करने की अनुमति देती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे छिपे हुए खर्चे समाप्त होंगे और दलालों पर निर्भरता घटेगी। उन्होंने कहा कि यह सुचारू और बाधारहित पंजीकरण प्रक्रिया नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों से मुक्त करने के उद्देश्य से बनाई गई है और यह योजना आपकी संपत्ति, आपकी सुविधाह्व के सिद्धांत पर आधारित है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मोहाली में सफलतापूर्वक शुरू की गई इस योजना को जल्द ही पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अपने 20 मिनट से अधिक समय के दौरे के दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और इस योजना पर फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से उनकी संपत्ति की रजिस्ट्री में लगने वाले समय के बारे में पूछा। नागरिकों ने अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए बताया कि उनका काम सुचारू रूप से और निर्धारित समय के भीतर पूरा हो गया, जिसकी जानकारी उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से मिलती रही। इस पहल की सराहना करते हुए कार्यालय में मौजूद नागरिकों ने कहा कि उनकी अर्जिय़ों को तुरंत और बिना किसी अनावश्यक देरी के निपटाया गया। उन्होंने आगे बताया कि कार्यालय में प्रवेश करने से लेकर रजिस्ट्रेशन पूरा होने और रजिस्ट्री दस्तावेज प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया में एक घंटे से भी कम समय लगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस अनूठी पहल की शुरूआत पर बधाई दी और कहा कि इससे पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सुचारू और कुशल हो गई है।

मुख्यमंत्री ने सरकारी दफ्तरों के कामकाज को और अधिक व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब लोग बिना किसी परेशानी के अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए ज़िले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जा सकते हैं। भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पहल तहसील कार्यालयों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि यह प्रणाली 15 जुलाई तक पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई से 1 अगस्त तक हर ज़िले में इस योजना का ट्रायल किया जाएगा और 1 अगस्त से इसे पूरे पंजाब में लागू कर दिया जाएगा, जिससे सभी नागरिकों को सुचारू रूप से रजिस्ट्रेशन सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी।

देश में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर होनी चाहिए सख्त कार्यवाही : ग्रेट खली

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। रेसलिंग की दुनिया का मशहूर नाम ग्रेट खली मंगलवार को करनाल पहुंचे। यहां पर मीडिया से बात करते हुए खली ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमारी सेना ने दिखा दिया कि मासुमों की जान लेने का नतीजा कितना मुश्किल होता है। रेसलर खली करनाल में लघु सचिवालय पहुंचे थे।

ग्रेट खली ने कहा कि जिस तरह से भारत तरक्की कर रहा है वो पकिस्तान को पसंद नहीं है। भारत की तरक्की के पीछे ही कम देश समर्थन दे रहे हैं। लेकिन सभी को पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का जन्मदाता है। पहलगाम में मारे गए विनय नरवाल के बारे में खली ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है। देश में कहीं भी जब कोई शहीद होता है तो उसकी शहादत हमेशा याद रहती है। वहीं पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले पर खली ने कहा जो देश के प्रति नफरत फैलाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

सम्पादकीय

चुनावी लड़ाई बना दिलचस्प

कागजों में लालू यादव के छोटे और हकीकत में बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी माता राबड़ी देवी के लाडले बेटे माने जाते हैं। बिहार की राजनीति को और खासकर लालू यादव के परिवार को करीब से देखने वाले जानकारों की माने तो, वर्ष 2015 में जब नीतीश कुमार की सरकार में तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री बनाया गया था,तभी से रिश्तों में यह खटास शुरू हो गई थी। तेज प्रताप यादव, बड़े बेटे होने के नाते अपने आपको लालू यादव का उत्तराधिकारी मान कर चल रहे थे लेकिन लालू यादव ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। कई जानकार लोग तो यहां तक कहते हैं कि राबड़ी देवी ने अड़ कर तेज प्रताप यादव को जेडीयू-आरजेडी गठबंधन सरकार में मंत्री बनवाया था। ऐसे में अपने ही बेटे के खिलाफ लालू यादव द्वारा लिए गए एक्शन को काफी आश्चर्य से देखा जा रहा है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या लालू यादव ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव के दबाव में यह फैसला लिया है ? एक तरफ जहां इस फैसले के लिए यादव परिवार के एकजुट होने का दावा किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ किसी को इसका भरोसा नहीं हो पा रहा है कि राबड़ी देवी अपने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से निकालने पर तैयार हो गई होंगी? तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट से लालू यादव इतना बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं,यह कोई सोच भी नहीं सकता था। तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर ऐलान कर दिया था कि वो एक लड़की के साथ 12 साल से रिलेशन में हैं और वो दोनों एक–दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट कर यह दावा किया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था और उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उसके बाद तेज प्रताप यादव के उस लड़की के साथ कई तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे,जिससे यादव परिवार को असहज कर दिया। बिहार में तय समय के अनुसार, अक्टूबर–नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। एक दौर में बिहार की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले लालू यादव इतनी तुरंत समझ गए कि बड़े बेटे की हरकतों का खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। पोस्ट और वायरल होते फोटो एवं वीडियो ने तेजस्वी यादव को भी इस बात का अहसास करा दिया कि अगर अब बड़े भाई पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो बिहार में एक बार फिर से उन्हें जनता विपक्ष में बैठने का ही जनादेश देगी। लालू यादव भी बेटे तेजस्वी यादव के तर्कों से सहमत हो गए और आखिरकार उन्होंने परिवार और पार्टी के मुखिया होने के नाते यह बड़ा फैसला कर लिया। लालू यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट और उसके बाद तेजस्वी यादव के आए बयान से आप समझ सकते हैं कि इस समय दोनों नेताओं के मन में बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव ही चल रहा है। क्योंकि दोनों ही नेता बिहार में एक और चुनावी हार को झेलने की स्थिति में नहीं है। लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को निकालने की घोषणा करते हुए लिखा, "निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला–बुरा और गुण–दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। लोकजीवन में लोकलाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद।" इसके बाद तेजस्वी यादव ने भी मीडिया के सामने आकर बयान दिया, "हमें यह सब चीज ना तो अच्छी लगती है और ना ही हम इसको बर्दाश्त करते हैं। जहां तक मेरे बड़े भाई की बात है, वह एडल्ट हैं उनको अधिकार है वह क्या निर्णय लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष (लालू यादव) ने उनके बारे में क्या कहा है, वह सार्वजानिक कर दिया गया है। वह अपने निजी जीवन में क्या कर रहे हैं यह हम किसी से पूछ कर नहीं करते हैं। आपके माध्यम से ही हमें यह पता चला है।" लालू यादव और तेजस्वी यादव भले ही तेज प्रताप यादव की प्रेम कहानी से पल्ला झाड़ने की कोशिश करें लेकिन यह विवाद अभी थमने वाला नहीं है। कई नाम हवा में तैर रहे हैं और एनडीए गठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा–हम के संस्थापक संरक्षक जीतन राम मांझी ने बड़ा खुलासा कर इस विवाद को और ज्यादा गरमा दिया है। केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "दरोगा बाबू की पोती ऐश्वर्या के साथ जो लालू परिवार ने किया है उसका बदला आने वाले चुनाव में बिहार की हर महिला लेकर रहेंगी। तेज प्रताप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में थें तो फिर किसी लड़की की ज़िन्दगी बर्बाद करने का अधिकार लालू परिवार को किसने दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी 'सिन्हा' के चक्कर में लालू परिवार अनुष्का यादव की ज़िंदगी भी बर्बाद करवा दे? इसका जवाब लालू परिवार को देश के सामने देना होगा।" जीतन राम मांझी की यह पोस्ट साफ–साफ बता रही है कि लालू यादव द्वारा अपने बेटे को बाहर निकालने के बावजूद यह विवाद अभी थमने वाला नहीं है। क्योंकि बिहार और केंद्र, दोनों जगहों पर सरकार चला रहे एनडीए गठबंधन के नेताओं के पास कुछ और भी नाम हैं।

जयंती

वीर सावरकर

जन्म–28 मई, 1883, भगूर गाँव, नासिक; मृत्यु–26 फरवरी, 1966, मुम्बई, भारत) न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे बल्कि एक भाषाविद, बुद्धिवादी, कवि, अप्रतिम क्रांतिकारी, दृढ राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, दार्शनिक, द्रष्टा, महान कवि और महान इतिहासकार और ओजस्वी आदि वक्ता भी थे। उनके इन्हीं गुणों ने महानतम लोगों की श्रेणी में उच्च पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया।

पुण्यतिथि

गोपाल प्रसाद व्यास

जन्म–13 फरवरी, 1915, गोवर्धन, मथुरा; मृत्यु–28 मई, 2005, नई दिल्ली) भारत के प्रसिद्ध कवियों, लेखकों और साहित्यकारों में से एक थे। वे ब्रजभाषा के कवि, समीक्षक, व्याकरण, साहित्य-शास्त्र, रस-रीति, अलंकार, नायिका-भेद और पिंगल के मर्मज्ञ माने जाते थे। पंडित जी हिन्दी में व्यंग्य–विनोद की नई धारा के जनक थे। गोपाल प्रसाद व्यास हास्य रस में पत्रीवाद के प्रवर्तक माने जाते थे। वे सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक व्यंग्य–विनोद के प्रतिष्ठ प्रसिद्ध कवि एवं लेखक थे और 'हास्यरसावतार' के नाम से प्रसिद्ध थे।

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-संजय कुमार द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।
RNI No. : DELHI/2016/70240
Phone No.: 9871221635
E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com
(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

नये आर्थिक सूरज बनने के सुखद एवं गौरवपूर्ण पल

सशक्त एवं विकसित भारत निर्मित करने, उसे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने और अर्थव्यवस्था की सुनहरी तस्वीर निर्मित करने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया, उनके अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है

–ललित गर्ग

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने रविवार की सुबह नये उगते सूरज के साथ भारत के नये आर्थिक सूरज बनने की सुखद एवं आह्लादकारी खबर दी। उन्होंने बताया कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब अगले ढाई से तीन वर्षों में जर्मनी को हटाकर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी बन चुके भारत ने अनेक नवीन संभावनाओं एवं उपलब्धियों को पंख लगाये हैं। निश्चित ही भारत आर्थिक क्षेत्र के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में एक महाशक्ति बन कर उभर रहा है, जो हर भारतीय के लिये गर्व एवं गौरव की बात है।

सुब्रह्मण्यम ने कहा, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी ही हमसे बड़े हैं और जो योजना बनाई जा रही है, अगर हम उसी पर टिके रहते हैं, अपनी योजनाओं एवं नीतियों को आगे बढ़ाते है तो भारत शीघ्र ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 में कहा था कि 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी बढ़कर 4,187.017 अरब डॉलर हो जाएगी। वहीं, जापान की जीडीपी का आकार 4,186.431 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार, आने वाले वर्षों में भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर सकती है और इस दौरान जीडीपी का आकार 5,069.47 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। वहीं, 2028 तक भारत की जीडीपी का आकार 5,584.476 अरब डॉलर होगा, जबकि इस दौरान जर्मनी की जीडीपी का आकार 5,251.928 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। आईएमएफ के मुताबिक, 2025 में अमेरिका 30,507.217 अरब डॉलर के आकार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वहीं, चीन 19,231.705 अरब डॉलर के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा।

भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से विश्व स्तर पर कई महत्वपूर्ण प्रभावों में बढ़ोतरी होगी। भारत का अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे जी 20 और आईएमएफ में प्रभाव बढ़ेगा। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) में और वृद्धि होगी, क्योंकि ग्लोबल कंपनियां भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में देख रही हैं। इससे भारत और जापान के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी, जैसे क्वाड्रन-5 और सैन्य सहयोग, भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। भारत इस उपलब्धि के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में और करीब आ गया है। भारत अगर 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देता है तो लीडरशिप और मजबूत होगी। भारत विश्वगुरु बनने एवं विश्व नेतृत्व करने में सक्षम होगा। भारत ने जापान को पछाड़ कर जो छलांग लगायी है, इसके पीछे जापान की अर्थव्यवस्था के सामने कई चुनौतियां रही है। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार, 2025 में जापान की जीडीपी ग्रोथ रेट केवल 0.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो भारत की 6.5 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। जापान की उम्रदराज आबादी और लो वर्थ रेट ने लेबर फोर्स को सीमित कर दिया है। अमेरिका और अन्य देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ और व्यापार नीतियों ने जापान की निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। जापान की अर्थव्यवस्था कई दशकों से स्थिरता के लिए संघर्ष कर रही है, जिसके कारण वह भारत जैसे तेजी से बढ़ते देशों से पिछड़ गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह भी कहा कि भारत की विकास दर 2025 में 6.2 प्रतिशत और 2026 में 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो कि बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ज्यादा है। इससे स्पष्ट है कि भारत अब सिर्फ जनसंख्या में ही नहीं, अर्थव्यवस्था के मामले में भी दुनिया में सबसे आगे निकलने की रेस में है। ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ने से ये विकास दर बनी रहेगी। हालांकि, ग्लोबल अनिश्चितता और ट्रेड टेंशन की वजह से इसमें थोड़ा असर पड़ सकता है।

सशक्त एवं विकसित भारत निर्मित करने, उसे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने और अर्थव्यवस्था की सुनहरी तस्वीर निर्मित करने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया, उनके अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। मोदी सरकार की नियोजित एवं दूरगामी सोच का ही परिणाम है रिजर्व बैंक के पास सोने के भंडार में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत में आर्थिक गतिविधियां नये शिखरों पर सवार है, क्योंकि भारत में डीमैट खाते 19 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं। देश के कुल डीमैट खाते अब अन्य देशों की तुलना में नौवें स्थान पर हैं, जिसका मतलब है डीमैट खाते रूस, जापान, इथियोपिया, मैक्सिको जैसे देशों की आबादी से अधिक और बांग्लादेश की आबादी के करीब है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 1,40,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप और हर 20 दिन में एक यूनिकॉर्न उभरता है। यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप को कहा जाता है, जिनका मूल्यांकन एक अरब डॉलर हो जाता है। इन आर्थिक उजले आंकड़ों में जहां मोदी के विजन हर हाथ को काम का संकल्प साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से उजागर हो रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर भारत ने जापान को पीछे छोड़ चौथी अर्थ-व्यवस्था बन गयी है। भारत ने अनेक आर्थिक क्षेत्रों में नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। लेकिन भारत के सामने चुनौतियां भी नयी-नयी शक्लों में उभर रही है। नयी आर्थिक उपलब्धियों एवं फिजाओं के बीच धनाढ्य परिवारों का भारत से पलायन कर विदेशों में बसने का सिलसिला चिन्ताजनक है। पलायनवादी सोच के कगार पर खड़े राष्ट्र को बचाने के लिए राजनीतिज्ञों एवं नीति नियामकों को अपनी संकीर्ण मनोवृत्ति को त्यागना होगा। तभी समृद्ध हो या प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने ही देश में सुख, शांति, संतुलन एवं सह-जीवन का अनुभव कर सकेगा और पलायनवादी सोच से बाहर आ सकेगा। करोड़पतियों के देश छोड़कर जाने की 7500 की संख्या भले ही कुछ सुधरी है, लेकिन नये बनते, सशक्त होते एवं आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत के लिये यह चिन्तन का विषय होना ही चाहिए कि किस तरह भारत की समृद्धि एवं भारत की प्रतिभाएं भारत में ही रहे।

भारत के अति समृद्धशालियों की संख्या समूचे विश्व में सर्वाधिक है। इन समृद्धशालियों से उम्मीद यह की जाती है कि देश में रहकर समृद्धि हासिल करने वाले समय आने पर देश को लौटाएंगे भी। तभी देश आर्थिक दृष्टि से दुनिया की महाशक्ति बनने की दिशा में तीव्रता से गति कर सकेगा। सवाल यही है कि देश को लौटाने और फायदा देने का वक्त आता है तब धनाढ्यों में एकाएक विदेश में जाकर बसने की ललक कैसे और क्यों पैदा हो रही है? अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने के समय इस तरह की पलायनवादी सोच का उभरना व्यक्तिगत स्वार्थ, सुविधा एवं संकीर्णता को दशार्ता है। दुनियाभर में धन और निवेश प्रवासन के रुझान को ट्रैक करने वाली कंपनी की सालाना रिपोर्ट में अति समृद्ध भारतीयों का अपना सब-कुछ समेट कर हमेशा के लिए भारत से जुदा हो जाने का अनुमान अनेक प्रश्न खड़े करता है, सरकार को इन प्रश्नों पर गौर करने की जरूरत है।

सदियों पहले भारत एक विकसित सभ्यता एवं सोने की चिड़िया रहा है। भारत हर दृष्टि से समृद्ध देश रहा है। अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ने से पहले मध्यकालीन दौर में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी रहा। विदेशी आक्रांताओं ने देश को लूटा। इतिहास में झांकें, तो लग सकता है कि मौर्य साम्राज्य की तरह एक बार फिर भारत समृद्धि के शिखर पर आरोहण करते हुए नए आर्थिक सफर एवं दुनिया की बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होने के लिये साजो-सामान तैयार कर रहा है। मॉर्गन स्टेनली के विशेषज्ञों ने कुछ ही समय पहले कहा है कि अगले दस साल भारत के लिए कुछ वैसे ही तेज विकास का समय होगा, जैसे चीन ने 2007 से 2012 के बीच देखा। आज के भारत में राजनीतिक एकता और सैन्य सुरक्षा के साथ पूरे इलाके का एक आर्थिक तंत्र भी विकसित हो रहा है। आर्थिक समृद्धि का दौर शुरू हुआ है तो इसके बाधक तत्वों पर विचार करना ज्यादा जरूरी है।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

आत्महत्या करने वाले सभी छात्रों की सोचें

देश को चाहिए कि वरिष्ठ मनोवैज्ञानिकों की कोई प्रदेश स्तर पर ऐसी कोई संस्था बनाए तो तकनीकि शिक्षा के लिए कोचिंग करने वालों और तकनीकि शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र–छात्राओं के मानसिक स्तर की समय–समय पर जांच करे। उनकी कोंसलिंग करे। उनकी समस्याओं पर विचार कर छात्र–छात्राओं का सही मार्ग दर्शन करे, ताकि वह आत्महत्या न कर, विपरीत परिस्थिति से संघर्ष करना सीखें

–अशोक मधुप

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कोटा में हुई छात्रों की मौत पर सुनवाई की। इन पर चिंता जाहिर की। स्टूडेंट्स सुसाइड के मामलों को भी गंभीर बताया और राजस्थान सरकार को फटकार लगाई, जबकि अकेले कोटा ही नहीं देशभर के छात्रों की मौत पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन मौत की जांच होनी चाहिए। देशभर के छात्रों की आत्महत्या और इनको रोकने पर विचार होना चाहिए।

स्टूडेंट्स सुसाइड मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कोटा में हो रहे स्टूडेंट्स सुसाइड के मामलों को भी गंभीर बताया और राजस्थान सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा, 'कोटा में इस साल अब तक 14 स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं। आप एक राज्य के तौर पर इसे लेकर क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स कोटा में ही क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? एक राज्य के तौर पर क्या आपने इस पर कोई विचार नहीं किया?' सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कोटा में छात्रा का शव मिलने और आईआटी खड़गपुर के छात्र के सुसाइड मामले की सुनवाई के दौरान की। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

चार मई को एनइइटी एग्जाम से कुछ ही घंटे पहले कोटा के हॉस्टल में 17 साल की छात्रा का शव मिला था। चार मई को ही, आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने वाले 22 साल के स्टूडेंट ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली थी। इन्हीं दोनों मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने छह मई को स्वतः संज्ञान लिया था। आईआईटी खड़गपुर सुसाइड को लेकर कोर्ट ने 14 मई को कहा था वो सिर्फ यह पता लगाने के लिए संज्ञान ले रहे हैं कि प्रशासन ने 'अमित कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य' मामले में जारी कोर्ट के निदेर्शों का पालन कर एफआईआर दर्ज कराई है या नहीं। वहीं, कोटा में हुए सुसाइड को लेकर कोर्ट ने जवाब मांगा था कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने ये सुनवाई की थी। इसी के साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश भी दिया था कि मेंटल हेल्थ और सुसाइड प्रिवेंशन के लिए बनने वाली नेशनल टास्क फोर्स यानी एनटीएफ के गठन के लिए 20 लाख रुपए दो दिन में जमा कराएं।

बात पिछले सालों की करें, तो साल 2024 में कोटा में रहने वाले 17 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। पिछले साल जनवरी के महीने में 2 और फरवरी के महीने में 3 सुसाइड हुए थे। वहीं साल 2023 में कोटा में स्टूडेंट सुसाइड के कुल 26 मामले सामने आए थे।

एमपी सुसाइड प्रिवेंशन टास्क फोर्स के मेंबर और साइकेट्रिस्ट डॉ सत्यकांत त्रिवेदी ने कोटा में हो रहे स्टूडेंट सुसाइड को लेकर कहा, किसी भी आत्महत्या का कोई एक कारण नहीं होता। वही एग्जाम सभी बच्चे दे रहे होते हैं। ऐसे में सुसाइड के लिए मिले-जुले फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। इसमें जेनेटिक्स कारण, सामाजिक कारण, पियर प्रेशर, माता-पिता के एक्सपेक्टेशन्स, शिक्षा तंत्र सब शामिल है। डॉ त्रिवेदी कहते हैं कि कहीं न कहीं हम बच्चों को ये सिखाने में नाकामयाब हो जाते हैं कि स्ट्रेस, रिजेक्शन या फेलियर से कैसे डील करना है। आज बच्चा ये मानने लगा है कि उसका एकेडमिक अचीवमेंट उसके एग्जिस्टेंस से भी बड़ा है। बच्चा तैयारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जीवन छोड़ने के लिए तैयार है। सोसायटी ने प्रतियोगी परीक्षाओं को बहुत ज्यादा महिमामंडित कर दिया है जिसकी वजह से बच्चा ये महसूस करता है कि मैं पूर्ण तभी हो सकूंगा जब कोई एग्जाम क्रैक कर लूंगा।

देश में आत्महत्या के हर साल आने वाले मामलों में छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। आंकड़ों की बात करें तो साल 2021 में 13,089 छात्रों ने आत्महत्या की थी, जबकि, साल 2022 में 13,044 छात्रों ने आत्महत्या की। वहीं 2018 से 2020 के दौरान कुल 33,020 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। भारत युवाओं का देश है। यहां की 60 फीसदी से ज्यादा आबादी युवा है, लेकिन, अब इसी देश में हर 40 मिनट में एक युवा अपनी जान दे रहा है। ये आंकड़े स्टूडेंट सुसाइड-एन एपिडेमिक स्वीपिंग इंडिया रिपोर्ट की ओर से जारी किए गए हैं। दरअसल, देश में हर दिन 35 से ज्यादा छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। साल 2018 से 2022 तक देश में 59,153 छात्रों ने आत्महत्या कर ली।

स्टूडेंट सुसाइड-एन एपिडेमिक स्वीपिंग इंडिया रिपोर्ट, आईसी थ्री की साला कॉन्फ्रेंस में साझा की गई। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। आईसी- 3 एक नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है।

इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में जहां आत्महत्या की दर हर साल दो फीसदी की दर से बढ़ रही है, वहीं छात्रों में आत्महत्या की दर चार फीसदी की दर से हर साल बढ़ रही है। यानी देश में आत्महत्या के जितने मामले हर साल आते हैं, उनमें छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। आंकड़ों की बात करें तो साल 2021 में 13,089 छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी, जबकि, साल 2022 में 13,044 छात्रों ने आत्महत्या की। वहीं 2018 से 2020 के दौरान कुल 33,020 छात्रों ने आत्महत्या की।

छात्रों की आत्महत्या के अलग-अलग मामलों में अलग-अलग वजहें हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में सिर्फ एक वजह है। ये वजह है मेंटल हेल्थ। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में 15 से 24 साल का हर सात में से एक आदमी खराब मेंटल हेल्थ की समस्या से जूझ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग अपनी मेंटल हेल्थ की समस्या को गंभीरता से नहीं लेते, यूनिसेफ के इस सर्वे में ही जितने लोगों ने भाग लिया, उसमें से सिर्फ 41 फीसदी लोग ही अपनी मानसिक समस्या के समाधान के लिए काउंसलर के पास गए। यानी 59 फीसदी लोगों ने इस समस्या को जैसे का तैसा छोड़ दिया।

देश को चाहिए कि वरिष्ठ मनोवैज्ञानिकों की कोई प्रदेश स्तर पर ऐसी कोई संस्था बनाए तो तकनीकि शिक्षा के लिए कोचिंग करने वालों और तकनीकि शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र-छात्राओं के मानसिक स्तर की समय-समय पर जांच करे। उनकी कोंसलिंग करे। उनकी समस्याओं पर विचार कर छात्र-छात्राओं का सही मार्ग दर्शन करे, ताकि वह आत्महत्या न कर, विपरीत परिस्थिति से संघर्ष करना सीखें। उन्हें जीवन जीने की कला सिखाई जाए। अगर विशेषज्ञ समझें तो कोचिंग करने वाले और तकनीकि शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को मेडिटेशन या ध्यान से भी जोड़ा जा सकता है। इससे युवाओं में विषय के प्रति एकाग्रता बढ़ेगी। चिंतन शक्ति का विकास होगा। निगेटिव विचार कम होंगे। ये मेडिटेशन या ध्यान उन्हें पूरे जीवन के लिए नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)
(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

दोस्त भारत का बदला रूस ने ट्रंप से लिया? पुतिन ने क्या बड़ा धमाका कर दिया

(एजेन्सी)।

यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले में रूस ने इतना विनाश किया कि अब उसकी लपटें अमेरिका तक जा रही हैं। तभी तो पुतिन के धमाके से ट्रंप भड़क गए। भारत का बदला लेने के लिए पुतिन अमेरिका पर दिन में करारा धमाका किया है। बात बात पर क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के फेर में रहने वाले ट्रंप फंस गए। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने का दावा करने वाले ट्रंप को पुतिन ने तगड़ा झटका दे दिया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि दोस्त भारत का बदला पुतिन ने अमेरिका से ले लिया है। सुपरपावर के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों हर देश के मामले में दखल दे रहे हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने जब पाकिस्तान में तबाही मचाई। आतंकी अड्डों और मुनीर सेना को सबक सिखाया तो उन्हें बचाने के लिए ट्रंप आगे आ गए और युद्धविराम का श्रेय लेने के लिए बयानबाजी करने लगे।

ट्रंप के क्रेडिट स्कोर को भारत की ओर से क्रेडिट स्कोर को दोस्त पुतिन ने सेटल कर दिया। जिसकी गवाही कीव से आ रही तस्वीरें दे रही है। जिसमें रूसी हमलों से यूक्रेन धुंआ धुंआ हो गया है। हुआ यूं था कि जब भारतीय सांसदों का एक डेलीगेशन रूस पहुंचने वाला था तभी यूक्रेन ने ड्रोन से मॉस्को एयरपोर्ट पर अटैक कर दिया। यूक्रेनी हमलों से रूस की 153 उड़ानें प्रभावित हुईं। भारतीय डेलीगेशन वाला प्लेन भी 40 मिनट तक आसमान में चक्कर काटता रहा। पुतिन ने इसके जवाब में यूक्रेन पर स्कंदर मिसाइल दागी। जिससे अमेरिका से मिले पैट्रिट डिफेंस सिस्टम की दो यूनिट ध्वस्त हो गई।

जिसके बाद रूस ने तीन साल से जारी युद्ध के दौरान रिकॉर्ड संख्या में ड्रोन भेजकर यूक्रेन पर हमला किया। यूक्रेन के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। यूक्रेनी वायु सेना के संचार विभाग के प्रमुख यूरी इहनात ने बताया कि रूस ने हमले के लिए 355 ड्रोन भेजे थे।

यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रविवार रात के हमले के दौरान रूस ने नौ क्रूज मिसाइलें भी दागीं। अधिकारियों ने बताया कि कुछ नागरिक घायल हुए हैं। हालांकि, हमले में तत्काल किसी के मारे जाने की सूचना नहीं है। रूस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शनिवार की रात यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य क्षेत्रों पर रूस के ड्रोन और मिसाइलों के संयुक्त हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए थे।

आईपीएल 2025 फाइनल में गूंजेगा 'जय हिंद'!

(एजेन्सी)।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों, शीर्ष रैंक वाले अधिकारियों और सैनिकों को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के फाइनल के लिए निमंत्रण भेजा गया है, जो 3 जून को अहमदाबाद में होगा। आईपीएल का खिताबी मुकाबला 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार तनाव के कारण टूनार्मेंट के चल रहे संस्करण को 9 मई को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया था। बीसीसीआई द्वारा यह कदम ऑपरेशन की सफलता का जश्न मनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सैकिया ने एएनआई को बताया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए अहमदाबाद में होने वाले आईपीएल फाइनल के लिए सभी भारतीय सशस्त्र सेना प्रमुखों (जनरल उपेंद्र द्विवेदी, थल सेना प्रमुख, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, नौसेना प्रमुख और एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह, वायु सेना प्रमुख), शीर्ष रैंक के अधिकारियों और सैनिकों को आमंत्रित किया है।

ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की निर्णायक सैन्य प्रतिक्रिया थी। 7 मई को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर में जैश–ए–मोहम्मद, लश्कर–ए–तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। हमले के बाद, पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और जम्मू–कश्मीर में सीमा पार से गोलाबारी की और साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन हमलों का प्रयास किया, जिसके बाद भारत ने एक समन्वित हमला किया और पाकिस्तान के 11 एयरबेसों में रडार इंफ्रास्ट्रक्चर, संचार केंद्रों और हवाई क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया।

ट्रंप के ऑफर को नेतन्याहू ने ठुकराया, हमास मिसाइलें लेकर जंग में उतरा

(एजेन्सी)।

इजरायल। इजरायल ने गाजा पर जिस तरह से बमबारी की है। जिस तरह से वहां तबाही मचाई गई है। इससे गाजा में सबकुछ खत्म हो गया है। घरों के घर जमींदोज हो चुके हैं। लोग भूख से चिल्ला रहे हैं और उनकी जान जा रही है। जिसकी वजह से इजरायल पर युद्ध विराम का दबाव बनाया जा रहा है। इसी बीच एक खबर भी आई कि दोनों देशों के बीच युद्धविराम होने की संभावना है। लेकिन अब खबर ये है कि इजरायल ने गाजा में अमेरिका की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर इजरायल की ओर से बयान भी सामने आया है। इजरायल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नया सीजफायर और बंधक समझौता किसी भी इजराइली सरकार के लिए अस्वीकार्य है। हमास की ओर से सीजफायर के लिए ऐसी शर्तें लगाई गई हैं, जो इजरायल के युद्ध लक्ष्यों और बंधकों को छुड़ाने की क्षमता को कमजोर करेंगी।

हमास के एक करीबी फिलिस्तीनी अधिकारी ने सोमवार को रॉयटर्स को बताया कि हमास ने गाजा में युद्ध विराम के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। नया प्रस्ताव, जिसमें दस बंधकों की रिहाई और 70 दिनों के युद्ध विराम की बात कही गई है, हमास को मध्यस्थों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने

कहा कि यह प्रस्ताव मध्यस्थों के माध्यम से हमास को भेजा गया था और इसमें 70 दिन के युद्ध विराम और गाजा पट्टी से इजरायली सेना की आंशिक वापसी के बदले में दो समूहों में दस इजरायली बंधकों की रिहाई शामिल है। लेकिन इजरायल के इनकार के बाद गाजा में युद्ध रुकने की उम्मीदें कमजोर होती जा रही हैं। आपको बता दें कि गाजा में अक्टूबर 2023 से युद्ध चल रहा है।

युद्ध से 53 हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और भारी तबाही हुई है। इजरायली अधिकारी ने कहा कि ये समझौता हमास के सामने सरेंडर करने जैसा है। समझौते में पहले दिन केवल पांच जिंदा बंधकों को रिहा करने और 60 दिनों के बाद पांच और बंधकों को रिहा करने जैसी शर्तें हैं। इसके अलावा अमेरिका की निगरानी में इजरायल को अपनी सेना को दो महीने पहले की स्थिति में वापस बुलाने और गाजा में व्यापक मानवीय सहायता पहुंचाने की शर्त है।

परेश रावल मेरे अच्छे दोस्त–अक्षय

(एजेन्सी)। अभिनेता अक्षय कुमार ने परेश रावल के उनकी फिल्म 'हेरा फेरी 3' से बाहर होने के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। अभिनेता अपनी फिल्म 'हाउसफुल 5' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में मौजूद थे, जहाँ उन्होंने रावल के फिल्म छोड़ने के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब दिया। कुमार ने कहा कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है और इसलिए, वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालाँकि, उन्होंने कहा कि उन्हें किसी के द्वारा रावल को नाम से पुकारे जाने की 'सराहना' नहीं है। आगामी फिल्म 'हेरा फेरी 3' से अभिनेता परेश रावल के बाहर होने पर अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि मैं अपने एक सह–कलाकार के लिए 'मूर्ख' जैसे शब्दों का उपयोग करना पसंद नहीं करता, जिनके साथ मैंने 30–32 वर्षों से अधिक समय तक काम किया है। उन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, वह बहुत अच्छे अभिनेता हैं, और मैं वास्तव में उनकी प्रशंसा करता हूं। विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह

एक गंभीर मामले के बारे में बात करने की जगह है, जिसे अदालत संभालेगी। इससे पहले रावल की टीम ने एक बयान जारी कर बताया था कि उन्होंने एक भी दिन शूटिंग नहीं की और फिल्म छोड़ते समय साइनिंग अमाउंट भी लौटा दिया। 69 वर्षीय रावल, जो 'हेरा फेरी' फ्रैंचाइज की दोनों फिल्मों का हिस्सा थे, ने सोशल मीडिया पर फिल्म छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की। हालांकि, उन्होंने कहा कि उनके फैसले का निर्देशक प्रियदर्शन के साथ किसी भी 'मतभेद' से कोई लेना–देना नहीं है। 'हेरा फेरी 3' छोड़ने के पीछे की असली वजह अभी भी स्पष्ट नहीं है।

आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ी, 15 सितंबर तक मिलेगा मौका

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जिन व्यक्तियों और संस्थाओं को अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना होता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा, अधिसूचित आईटीआर में किए गए व्यापक बदलावों तथा आकलन वर्ष 2025-26 के लिए प्रणाली की तैयारी एवं आईटीआर सुविधाओं के जारी होने के लिए आवश्यक समय को देखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ा दी गई है। सीबीडीटी ने कहा, 'करदाताओं के लिए दस्तावेज दाखिल करने के अनुभव को सुचारू एवं सुविधाजनक बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि जो मूल रूप से 31 जुलाई थी उसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है।'

चेयरमैन फात्मा रजा के अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित

संजना भारती संवाददाता

बदायूँ। पूर्व मंत्री आबिद रजा ने कहा कि जिस विश्वास से शहर की जनता ने फात्मा रजा को निर्दलीय रूप में वोट देकर बदायूँ शहर का चेयरमैन चुना मुझे खुशी है कि उस विश्वास पर चेयरमैन फात्मा रजा खरी उतरी। फात्मा रजा ने दो साल में नगर पालिका से सम्बन्धित पानी सफाई, स्ट्रीट लाईट सड़कों में सुधार हुआ जिसके लिए फात्मा रजा व नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी बधाई के पात्र है। फात्मा रजा को विशेष रूप से इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि उन्होंने शहर का विकास बिना भेदभाव के किया।

फात्मा रजा ने दो साल पूरे होने पर अपने सम्बोधन में कहा कि जब में चेयरमैन बनी तब पालिका पर लगभग दस करोड रुपये कर्मचारियों की देनदारी थी पांच साल से कर्मचारियों का बोनस नहीं दिया है। हमने अपने कार्यकाल में पिछले पांच साल के बोनस के साथ-साथ लगभग छः करोड़ रुपये की कर्मचारियों के बकाये का भुगतान किया।

पानी के क्षेत्र में तीन ओवर हैण्ड टैंक बनवाये जा रहे है। चार मिनी टयूवेल बनवा दिये गये है लगभग छोटे बड़े मिलाकर 10-12 टयूवेल का निर्माण किया जा रहा है। सफाई के क्षेत्र में आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को रखकर सफाई व्यवस्था में सुधार जनता को नजर आ रहा होगा। शहर की स्ट्रीट लाईट व्यवस्था बेहद खराब थी शहर में स्ट्रीट लाईट लगाकर तथा खराब पड़ी फैन्सी लाईटों को ठीक करा दिया गया अभी भी लाईट के क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। वह भी जल्द ही स्ट्रीट लाईट बेहतर करायी जायेगी। पूरे शहर के मुख्य मार्गो से लेकर गलियां टूट पड़ी थी। दो साल में जनता को सड़को में सुधार आ रहा है। जल भराव की समस्या से निजात के लिए शहर में युद्ध स्तर पर पालिका द्वारा नालों का निर्माण कराया जा रहा है।

फात्मा रजा ने अपने सम्बोधन में यह भी कहा कि पालिका द्वारा पानी स्ट्रीट लाई सफाई, सड़क के क्षेत्र में जो सुधार आ रहा है उसमें अहम भूमिका सम्बन्धित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की है मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं। जनता को पालिका से सम्बन्धित छोटे-छोटे कार्यों के लिए अलग-अलग पटल पर जाना पड़ता था उसके लिए मेरे आदेश एकल खिड़की पालिका में बना दी गयी है जिससे जनता को राहत मिली। जो शहर में अधूरा कार्य है मेरा प्रयास होगा कि अगले तीन वर्षों में हम उसे पूरा कर सकें। फात्मा रजा ने सभी सभासदों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

इस मौके पर सभासद अनवर खॉ, गिरीश शुक्ला, वाहिद अली अनवर अन्सारी, शाजमा, मोह.नईम, भागदेवी, भूदेवी चन्देल, लियाकत अली ममता, राजीव नारायन, मनोज कश्यप, किशोर, जया साहू,जीनत बी, मुकेश साहू, अख्तरी बेगम, मोहित सक्सेना, अरविन्द राठोर रेशमदेवी आशीष कश्यप नाजरीन अवर अभियन्ता (सिविल) कृष्ण गोपाल चन्द्रा, मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक गो० तम्यब, सफाई निरीक्षक राजीव मलिक केशव गंगवार, राजस्व निरीक्षक लवी कुमार राजेन्द्र सिंह कार्यालय अधीक्षक खालिद अली खॉं. लिपिक नवेद इकबाल गनी सचिन सक्सेना, सूर्य प्रकाश सक्सेना, रजनीश चन्द्र, जहांगीर, सुमित सिंह, विनोद प्रकाश सोनकर, महेश बाबू, मनोज सोनकर मनोज सक्सेना, देवेन्द्र सक्सेना एवं पूर्व डीजीसी जवाहर सिंह यादव, जिलाबार अध्यक्ष पवन गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष ओमवीर सिंह यादव, नगर अध्यक्ष फरहत अली, सोहिल सिद्दीकी, हर्षित यादव, एडवोकेट भानु यादव, सोमेन्द्र यादव आदि समेत शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

आखिरकार डीईओ संजय कुमार हुए निलंबित, पूर्वी चम्पारण के कई अधिकारी रडार पर

संजना भारती संवाददाता

मोतिहारी। कहते है कि देर है पर अंधेर नहीं...देर ही सही आखिरकार पूर्वी चम्पारण के तत्कालीन व पटना के वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार निलंबित हो ही गए।

विभागीय विशेष सचिव सह निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि उप विकास आयुक्त पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 683 दिनांक 09-04-25 द्वारा जिला पदाधिकारी को समर्पित जांच प्रतिवेदन में तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप यथा बेंच-डेस्क की गुणवता असंतोषजनक पाया जाना, सभी वृहत मरम्मती कार्य से संबंधित प्राकलन नहीं पाया जाना, अभिलेख में त्रुटिपूर्ण कार्यादेश पाया जाना, बिना हस्ताक्षरित कोटेशन जैसे लापरवाही बरतना, संचिका का लापरवाहिपूर्ण तरीके से संधारण करना, कार्य में शिथिलता बरतने आदि गंभीर आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। जिसके कारण पूर्वी चम्पारण के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के तहत निलंबित किया जाता है।

गौरतलब हो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ठेकेदार बनकर भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए थे। जिसकी चर्चा मोतिहारी 20 सूत्री की बैठक में कई विधायकों ने किया था जिसको लेकर शिक्षा विभाग के मंत्री लाह प्रभारी मंत्री सुनील कुमार ने मोतिहारी के जिलाधिकारी को पत्र लिखा और जांच कर तीन हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा था परंतु जांच टीम भले ही गठित हो गई थी, पंद्रह दिनों में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा गया था लेकिन वह फाइल भी दबा दी गई थी।

जिला शिक्षा कार्यालय ने पूर्व डीईओ संजय कुमार के खिलाफ जांच से संबंधित फाइल जांच टीम को देने में काफी विलंब हुई थी जिसके कारण श्री कुमार के निलंबन में विभाग को इंतजार करना पड़ा।

वही विभागीय सूत्रों की माने तो बेंच डेस्क भुगतान व आपूर्ति मामले में पूर्वी चम्पारण के कई अधिकारी शिक्षा विभाग व निगरानी विभाग के राडार पर है और सीघ्र ही इसकी सूचना मिलने की संभावना जताई जा रही है।

अग्नि पीड़ित परिवार को दी राहत सामग्री

संजना भारती संवाददाता

दलसिंहसराय/समस्तीपुर। शहर के बाजार समिति रोड में दुर्गा मंदिर के सामने मुसहरी टोला में बीते 25 मई को एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया। जिसमें एक घर में आग लगी और उसमें दो बच्चे थे जो जल कर खत्म हो गए। इस घटना में शंभू मांझी और फूलों देवी के तीन संतानों में से 2 संतानों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस भीषण दुर्घटना से उनका पूरा परिवार गहरे सदमे में है। घर, कपड़े और बर्तन तक जल गए।

घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय 'श्रीराजेंद्र प्रसाद ट्रस्ट' के सदस्यों ने एक बैठक कर यह तय किया कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। पीड़ित परिवार की सहायता हेतु ट्रस्ट के सचिव गिरीश सर्राफ की अगुवाई में अमित मालाकार, संजय ठाकुर, चंदन पोद्दार, ट्रस्ट के फाउंडर डॉ. संजीव प्रकाश, उपाध्यक्ष रोहन प्रकाश, सह सचिव आकाश आनंद के साथ अजीत कुमार साह, सुभाष कुमार सोनी, पवन कुमार, गुड्डू ठाकुर, आनंद कुमार सोनी, संतोष कुमार, मनोज कुमार सोनी भी मौजूद थे।

इस क्रम में अमित मालाकार के हाथों पीड़ित परिवार को जहां आर्थिक सहायता प्रदान की गई। वहीं पीड़ित परिवार के आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अमित मालाकार के द्वारा खाने की सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया। आनंद जी के द्वारा खाने के बर्तनों की व्यवस्था की गई, वहीं ट्रस्ट के ही जरिए कपड़े की व्यवस्था की गई। ट्रस्ट के सदस्य अजीत साह उर्फ छोटू ने गृह निर्माण में सहयोग का आश्वाशन दिया, जिसको आगे के चरणों में अंजाम दिया जाएगा। पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना जाहिर करते हुए ट्रस्ट के सदस्यों ने आश्वासन दिया कि श्रीराजेंद्र प्रसाद ट्रस्ट आगे भी जरूरत पड़ने पर आपके साथ खड़ा रहेगा।

बता दें कि श्रीराजेंद्र प्रसाद का निधन विगत 08 मई 2025 को उनके निवास पर हो गया था। उन्हें अपना प्रेरणा मानते हुए यह ट्रस्ट समाज के कुछ युवाओं के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें लोगों के भागीदारी का आधार जरूरतमंदों की मदद करना है और यह कार्य ट्रस्ट के सदस्य पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ पिछले 18 महीनों से कर रहे हैं।

पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें किया गया याद

संजना भारती संवाददाता

बेगूसराय। 27 मई को बेगूसराय प्रखंड के बंद्वार पंचायत में सुधीर सिंह की अध्यक्षता में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता श्रीकांत राय ने इस सभा की अध्यक्षता की। श्रीकांत राय ने इस मौके पर कहा कि दुनिया के इतिहास में पंडित नेहरू का व्यक्तित्व हमेशा स्वर्णाक्षरों में रहेगा। आजादी की लड़ाई से लेकर स्वतंत्र भारत को आधुनिक बनाने तक उनका योगदान अमिट रहेगा। प्रखंड अध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने कहा कि बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू ने स्वतंत्र भारत के विकास की जो बुनियाद रखी उस नींव पर आज हम दुनिया के बड़ी ताकत बन कर खड़े हैं। समाजवाद और वैज्ञानिकवाद के तालमेल से उन्होंने देश के विकास की जो गाथा लिखी वो अद्भुत है।

मौके पर मोती सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह, सहदेव सिंह, राम उदगार यादव, कौशल किशोर सिंह, सुखराम साह, फिलो सिंह, अनिल सिंह, मंटून यादव, मधुसूदन यादव, जय प्रकाश गुप्ता, नीरज तांती, वीडियो साह सहित अन्य लोग मौजूद थे।

बाल संरक्षण हेतु जिला स्तरीय बैठक में बाल श्रम, पोक्सो व बाल अधिकार संरक्षण पर दी कानूनी जानकारी

एसबी संवाददाता

बूंदी। जिले में हितधारकों के बीच बाल संरक्षण संबंधी प्रमुख कानूनों की समझ को बढ़ाने, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी एवं मानव तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों की रोकथाम करने

विभिन्न विभागों और संस्थाओं के बीच सहयोग व समन्वय स्थापित करने एवं बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से कार्यालय पुलिस अधीक्षक सभागार, बूंदी में एक जिला स्तरीय बैठक का आयोजन बलुआ पत्थर आपूर्ति श्रृंखला में बाल श्रम के उन्मूलन हेतु चल रही परियोजना के अंतर्गत किया गया। यह बैठक पुलिस विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं एक्शनएड एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस उपअधीक्षक जसवीर मीणा ने की। बैठक में श्रम विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास, महिला अधिकारिता, शिक्षा विभाग, चाइल्डलाइन, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस इकाई, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक संगठनों तथा समुदाय प्रतिनिधियों आदि ने भाग लिया।

प्रतिभागियों ने जमीनी अनुभव साझा करते हुए स्थानीय स्तर पर आने वाली चुनौतियों और समाधान पर चर्चा की।

कार्यक्रम के दौरान 1 जून से 30 जून 2025 तक चलने वाले विशेष अभियान "उमंग-V" का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी की रोकथाम, पीड़ित बच्चों की पहचान, बचाव, पुनर्वास और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। पुलिस उप अधीक्षक जसवीर मीणा ने कहा, "बाल श्रम और मानव दुव्यापार की रोकथाम सिर्फ कानूनी कार्रवाई का विषय नहीं है, यह सामाजिक उत्तरदायित्व है। हमें एकजुट होकर संवेदनशीलता और सजगता के साथ बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना होगा। बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। कोई भी बच्चा मजदूर नहीं, बल्कि देश का भविष्य है। समाज में जब तक संवेदनशीलता और जागरूकता नहीं होगी, तब तक इन बुराइयों का अंत संभव नहीं है। सहायक निदेशक बाल अधिकारिता हुकमचंद जाजोरिया ने किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 व पोक्सो एक्ट की प्रमुख धाराओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने इन कानूनों के उद्देश्य, बच्चों के अधिकारों की रक्षा में इनकी महत्ता, तथा इनकी व्यावहारिक क्रियान्वयन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने बाल संरक्षण में पुलिस की भूमिका को भी रेखांकित करते हुए कहा कि पुलिस की पहली प्रतिक्रिया, पीड़ित बच्चे के साथ व्यवहार, तथा समय पर की गई कानूनी प्रक्रिया बच्चे के मानसिक और शारीरिक पुनर्वास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि पुलिस अपने कार्य में पूरी संवेदनशीलता, समझ और मानवता के साथ कार्य करे, तो बाल अपराधों की रोकथाम संभव है और समाज में एक भी बच्चा पीड़ित नहीं रहे।

बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सीमा पोद्दार ने कहा कि बाल संरक्षण केवल सरकारी दायित्व नहीं, बल्कि हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने बाल कल्याण समिति की संरचना, कार्यप्रणाली व दायित्वों की जानकारी भी साझा की और बताया कि समिति कैसे जनसहयोग से हर बच्चे तक पहुंचने के प्रयास कर रही है।

एक्शन एड ज़िला समन्वयक जहीर आलम ने बाल अधिकार व बाल संरक्षण के बारे में जानकारी दी साथ ही बाल संरक्षण के मामलों में बाल अनुकूल संचार, बंद और खुले हुए प्रश्न का महत्व पर प्रकाश डाला इसके अतिरिक्त, उन्होंने सुझाव दिया कि सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रशिक्षण, जागरूकता और समन्वय की आवश्यकता है, जिससे बच्चों के प्रति अपराधों को प्रभावी रूप से रोका जा सके और न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

इस अवसर पर जेंडर विशेषज्ञ विनीता अग्रवाल, समन्वयक सवाराम ग्रासिया, मानव तस्करी विरोधी इकाई इंद्रा प्रजापति, राम नारायण, कॉन्सलर छाया सक्सेना, राम भवन गौतम, ओ डब्लू दीपिका वशिष्ठ, सुरेश भील, सुरेश रैगर, चाईल्ड लाईन से राम नारायण गुर्जर, सभी थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

महिला संवाद में समस्या से समाधान तक की हो रही हैं बातें

एसबी ब्यूरो प्रमुख/मृगांक शेखर सिंह

जमुई। जमुई में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित महिला संवाद कार्यक्रम के 40वें दिन मंगलवार 27 मई को जिला अंतर्गत विभिन्न पंचायतों के कुल 22 गाँव में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं की प्रबल भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं जीविका से जुड़कर अपने बदलाव की गाथा सुना रही हैं। इस कार्यक्रम में संवाद एक अनूठी पहल के रूप में निकल कर सामने आया है, जहाँ महिलाओं को अपनी बात रखने का मौका मिला है। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं का कहना है कि समाज के विकास के लिए आज हमें अपनी बात रखने का न सिर्फ मौका मिला है, बल्कि वे इस मंच के माध्यम से सामूहिक समस्या के निदान की बातें भी रख रही हैं।

महिला संवाद रथ के माध्यम से महिलाओं को महिला स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की सफलता की गाथा दिखाई जा रही है। यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं की आवाज को नीतिगत बदलावों तक पहुँचाने का सशक्त प्लेटफॉर्म भी बनता जा रहा है। महिलाओं की भागीदारी और उत्साह इस बात का प्रमाण है कि वे अब न केवल जागरूक हैं, बल्कि विकास की राह पर मजबूती से कदम बढ़ा रही हैं।

चकाई प्रखंड के दुलमपुर पंचायत के रौशनी ग्राम संगठन में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में वार्ड नंबर 3 बड़गुंडा गाँव की महिलाओं ने सामूहिक रूप से चकाई प्रखंड को रेलवे से जोड़े जाने की आकांक्षा व्यक्त की। सोनो प्रखंड के बाबुडीह पंचायत में आयोजित संवाद कार्यक्रम में महिलाओं को संवाद का उद्देश्य बताकर योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिलाओं को विडियो फिल्म के माध्यम से सरकार के द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया तथा लीफलेट के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रियान्वित महत्वाकांक्षी योजनाएं से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में शामिल सभी महिलाओं को घरेलु हिंसा नहीं करने एवं पीड़ित महिला का साथ देने, बाल-विवाह उन्नमूलन की रोकथाम हेतु शपथ दिलाया गया।

प्रखंड चकाई, झाझा, सोनो, लक्ष्मीपुर, सिकंदरा, ई. अलीगंज, जमुई सदर एवं खैरा प्रखंड में आयोजित संवाद कार्यक्रम में योजना से लाभान्वित महिलाओं के द्वारा अनुभव साझा किया गया, वही। महिलाओं ने अपने गाँव-मोहल्लों की समस्या को लेकर भी अपनी-अपनी आकांक्षाएं जाहिर की।

28 मई को आयोजित होने वाले प्रखंडवार महिला संवाद कार्यक्रम की सूची: चकाई (कल्याणपुर, माधोपुर) ई. अलीगंज (कैथा, कोल्हाना), जमुई सदर (इन्द्पे, कुन्दरी सकुहरा) झाझा (बैजला, बालियाडीह, छापा, माह्पुर), खैरा (भीमाइन, बिशनपुर, झुंडो, खरैंच), लक्ष्मीपुर (राधा, सावन), सिकंदरा (भुल्लो, गुखुला फतेहपुर), सोनो (बबुडीह, छूछनारिया, नैयाडीह, रजौन)।

सुपर मॉम्स व सुपर गर्ल्स प्रतियोगिता में मिला छिपी प्रतिभा दिखाने का मौका: मनप्रीत कौर

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आयोजित हुई सुपर मॉम्स और सुपर गर्ल्स डांस व मॉडलिंग प्रतियोगिता को लेकर शो की ब्रांड एंबेसडर व रोडीज सीजन 19 फेम मनप्रीत कौर ने कहा कि इस तरह के बहुत कम ही आयोजन होते हैं जहां लोगों की छिपी हुई प्रतिस्पर्धा को सामने लेकर आने का उन्हें मौका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता की थीम बिल्कुल ही अलग थी जिसको लेकर सभी सुपर मॉम्स में क्रेज था। उन्होंने कहा कि शो के आयोजक विजेश शर्मा व सीमा ठाकुर भविष्य में भी ऐसे आयोजन करवाते रहें यही उनकी कामना है।

यूनिवर्सल इवेंट प्लानर द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित सुपर मॉम्स व सुपर गर्ल्स प्रतियोगिता ने लूटी वाहवाही: मालती ठाकुर

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आयोजित हुई सुपर मॉम्स और सुपर गर्ल्स डांस व मॉडलिंग प्रतियोगिता पूरी ट्राई सिटी में ही नहीं बल्कि हिमाचल में पंजाब में भी खूब वाहवाही लूट रही है यह कहना है मशहूर मॉडल व शो ओपनर मालती ठाकुर का। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वह बहुत सारी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी है लेकिन इस प्रतियोगिता की थीम सबसे अलग थी। और इसके साथ ही आयोजक विजेश शर्मा व सीमा ठाकुर द्वारा अपनी हर प्रतियोगिता में दिव्यांगों को समाज में सम्मानित स्थान दिलवाने का जो प्रण लेकर दिव्यांगों को भी स्टेज तक लेकर आने और उनके अंदर छिपे हुए हुनर को लोगों के सामने लेकर आने का प्रयास भी सराहनीय है। इसके साथ ही मालती ठाकुर ने आयोजन की सफलता की आयोजकों को बधाई दी।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो सहनशीलता: 10000 रुपए रिश्वत लेता ए. एस. आई. विजीलैंस ब्यूरो द्वारा काबू

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा अपनाई गई जीरो सहनशीलता नीति के हिस्से के तौर पर पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने तरन तारन जिले के थाना सरहाली कलाँ में जांच अधिकारी (आई. ओ.) के तौर पर तैनात सहायक सब-इंस्पेक्टर (ए. एस. आई.) हरजीत सिंह को 10000 रुपए रिश्वत लेते हुये काबू किया है।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये आज यहाँ राज्य विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ़्तारी गाँव सरहाली के एक निवासी द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के उपरांत की गई है।

उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने दोष लगाया कि उसके विरुद्ध उक्त थाने में एक पुलिस केस दर्ज है और इस केस में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के उपरांत उक्त जांच अधिकारी ए. एस. आई. ने केस की जांच में शामिल होने सम्बन्धी 10,000-20,000 रुपए रिश्वत की माँग की थी।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस शिकायत की प्राथमिक तस्दीक के उपरांत विजीलैंस ब्यूरो की टीम ने एक जाल बिछा कर उक्त पुलिस मुलाजिम को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 10000 रुपए रिश्वत लेते हुये काबू कर लिया। इस सम्बन्धी मुलजिम के विरुद्ध विजीलैंस ब्यूरो के थाना, अमृतसर रेंज में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मुलजिम को कल समर्थ अदालत में पेश किया जायेगा और इस मामले की आगे जांच जारी है।

पटवारी का सहायक 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों काबू

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आज पटवारी रणजीत सिंह के सहायक सुखा को जमीनी रिकॉर्ड में सुधार के बदले 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इस संबंध में आज यहां जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को कपूरथला शहर के एक निवासी द्वारा दी गई शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने एक बैंक से 10 लाख रुपए का मकान लेने के लिए ऋण हेतु आवेदन किया था। सत्यापन के दौरान उसकी संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों में खसरा और फर्द नंबरों में अंतर पाया गया, जिसके बाद उसने तहसील कार्यालय में सुधार के लिए आवेदन दिया। तहसीलदार ने उसका आवेदन कार्रवाई हेतु पटवारी रणजीत सिंह को भेज दिया। प्रवक्ता ने बताया कि जब शिकायतकर्ता ने पटवारी के उक्त सहायक सुखा से संपर्क किया, तो उसने रिश्वत की पेशगी राशि के तौर पर 1000 रुपए की मांग की और 4-5 दिनों में काम पूरा करने का वादा किया। तीन दिन बाद सुखा ने शिकायतकर्ता को बताया कि अब इस काम के लिए 6000 रुपए की और रिश्वत देनी पड़ेगी। इससे परेशान होकर शिकायतकर्ता ने 26 मई को सीधे पटवारी रणजीत सिंह से संपर्क किया, जिसने उसे फिर से सुखा के पास भेज दिया।

महाराणा प्रताप का जीवन साहस, बलिदान और राष्ट्र के प्रति निष्ठा का अनुपम उदाहरण: योगेंद्र राणा

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। असंध विधानसभा क्षेत्र के विधायक योगेन्द्र राणा मंगलवार को करनाल कोर्ट परिसर पहुंचे, जहाँ उन्होंने अधिवक्ताओं एवं जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों से भेंट कर उन्हें 29 मई को सालवन में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप जयंती समारोह में सादर आमंत्रित किया।

समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। यह समारोह न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि युवाओं में देशभक्ति, स्वाभिमान और संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाने का माध्यम भी बनेगा। विधायक राणा के करनाल कोर्ट परिसर आगमन पर जिला बार एसोसिएशन ने उनका भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं, तालियों और गर्मजोशी भरे अभिवादन के साथ वकीलों ने उन्हें सम्मानित किया। वकीलों ने विधायक के समाज सेवा और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। विधायक योगेन्द्र राणा ने अपने संबोधन में कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन साहस, बलिदान और राष्ट्र के प्रति निष्ठा का अनुपम उदाहरण है। उनकी जयंती न केवल एक उत्सव है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। इस समारोह में आपकी उपस्थिति ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से अपील की कि वे बड़ी संख्या में सालवन पहुंचकर समारोह की गरिमा को और ऊँचा उठाएं तथा राष्ट्रभक्ति की भावना को सशक्त करें। जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने विधायक राणा को विश्वास दिलाया कि वे पूरे उत्साह और सम्मान के साथ भारी संख्या में समारोह में उपस्थित होकर इसे ऐतिहासिक बनाएंगे।

इस अवसर पर कोर्ट परिसर में एक उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। वरिष्ठ अधिवक्ताओं, बार पदाधिकारियों, युवा वकीलों और गणमान्य नागरिकों ने एक स्वर में कहा कि महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों की जयंती का आयोजन समाज में नई चेतना और प्रेरणा भरने का कार्य करता है। विधायक राणा के इस प्रयास की चारों ओर सराहना हो रही है और सालवन में होने वाले इस राज्य स्तरीय समारोह को लेकर जनमानस में उत्साह चरम पर है।

इस अवसर पर राजपूत सभा के जिलाध्यक्ष डॉ एनपी सिंह, एसोसिएशन के प्रधान सुरजीत सिंह मधान, राजकुमार चौहान, नितिन भारद्वाज, नवीन कुमार राणा, संगीता, सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

'मिशन बुनियाद' ओपनिंग सेरेमनी हरियाणा में प्रदेश स्तर पर आयोजित हुई

मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी

■ राजौंद में आयोजित ओपनिंग सेरेमनी में पहुंचे ब्लाक शिक्षा अधिकारी बलबीर सिंह कश्यप व स्कूल प्रिंसिपल भूपेंद्र सिंह

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। मंगलवार, 27 मई को हरियाणा प्रदेश में 'मिशन बुनियाद' की नवमी में दाखिला ले चुके विद्यार्थियों के लिए ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। खंड राजौंद के शहीद सियाराम संस्कृत मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

राजौंद में आयोजित ओपनिंग सेरेमनी में पहुंचे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजौंद बलबीर सिंह कश्यप ने विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूल की आठवीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी तीन स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा को पास करके 'मिशन बुनियाद" में दाखिला ले सकता है। पूरे हरियाणा में अपने-अपने खंड स्तरीय स्टडी सेंटर पर आयोजित ओपनिंग सेरेमनी में पात्र विद्यार्थियों ने भाग लिया हैं। उन्होंने बताया कि मिशन बुनियाद में नौवीं व दसवीं में पढ़ रहे विद्यार्थी व हरियाणा के किसी भी सरकारी स्कूल से नवमी व दसवीं में कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी आगे चलकर 'सुपर सौ" में दाखिले के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों के गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों को 'मिशन बुनियाद' व 'सुपर सौ' बेहतरीन योजनाएं शुरू की है। जो विद्यार्थियों को उनके स्वप्न साकार करने का एक सुनहरा अवसर दिया है। विद्यार्थियों को इसमें जरूर भाग लेना चाहिए।

इस अवसर पर पहुंचे शाहिद सियाराम संस्कृत मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल भूपेंद्र सिंह ने बताया कि "मिशन बुनियाद" हरियाणा के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को अपने भविष्य के लिए बेहतरीन प्लानिंग करने व उस प्लानिंग पर खरा उतरने, अपने, परिवार व गुरूजनो के स्वप्नों को साकार करने का अवसर देते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हुई है। विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल में पढ़कर इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। जो विद्यार्थी हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कक्षा आठवीं में पढ़ रहे रहे हैं, उनके फार्म कक्षा आठवीं में पढ़ते हुए "मिशन बुनियाद" की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भरे जाते हैं। तीन स्तरिय प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके विद्यार्थी मिशन बुनियाद का हिस्सा बन सकता है। उनका दाखिला "मिशन बुनियाद" में कक्षा नौवीं में होता है। मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी व उनके काबिल शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं "सुपर सौ" डायरेक्टर नवीन मिश्रा, "मिशन बुनियाद" डायरेक्टर प्रदीप सेंसेरवाल व उनकी टीम ने हरियाणा के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को हौसलों की उड़ान भरने के लिए खुला आसमान दिया है। अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए यह महत्वाकांक्षी योजना "मिशन बुनियाद" व उसके बाद "सुपर सौ" योजना, गरीब व मध्यवर्गीय परिवार के विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी हरियाणा सरकार ने बनाई है। जिसमें पढ़ाई, वर्दी, नि:शुल्क हरियाणा सरकार देती है। विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ जरूर उठाना चाहिए। जिनके दाखिले कन्फर्म हो गए हैं। उन्हें नियमित रूप से अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करने हेतु अलाट किए गए विद्यालय के सेंटर में पहुंचना चाहिए।

करनाल के विधायक जगमोहन आनंद ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात और विकास कार्यों पर की चर्चा

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। विधायक जगमोहन आनंद ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ स्थित आवास संत कबीर कुटीर में मुलाकात की और करनाल विधानसभा क्षेत्र में प्रगति पर चल रहे विकास कार्यों तथा भविष्य की विकास योजनाओं को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

विधायक जगमोहन आनंद ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पूर्ण विश्वास दिलाया कि करनाल के सर्वांगीण विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और करनाल विधानसभा क्षेत्र पहले की तरह ही सीएम सिटी के समान ही सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगा।

विधायक जगमोहन आनंद ने मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया और कहा कि जनता के लिए काम करना उनकी पहली प्राथमिकता है। जनता की समस्याओं को सुनना व उनका समाधान करना उनका पहला दायित्व है। उन्होंने बताया कि विकास के कार्यों को चेक किया जा रहा है तथा संबंधित अधिकारियों को लगातार विकास कार्यों से संबंधित बातचीत की जाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को करनाल के विकास का निरंतर गति प्रदान करने और जनहित को सर्वोपरि रखने की प्रतिबद्धता के लिए तथा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट किया।

बीआरसी कम बीईओ राजौंद बलबीर सिंह कश्यप का प्रमोशन के उपरांत हुआ स्थानांतरण

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। राजौंद में लंबे समय तक सेवाएं देने के पश्चात बीआरसी कम कार्यकारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बलबीर सिंह कश्यप का प्रमोशन के साथ स्थानांतरण हो गया है। जानकारी के अनुसार बलबीर सिंह कश्यप को खंड शिक्षा अधिकारी गुहला के रूप में अपनी सेवाएं देनी है। उनकी सेवानिवृत्ति/रिटायरमेंट 31 जनवरी 2026 को है। वे लगभग 8 महीने इस पद पर अपनी सेवाएं देंगे।

जानकारी के अनुसार राजौद में अनिल कुमार खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालेंगे। उनका प्रमोशन एवं स्थानांतरण बीआरसी खंड जुलाना, जिला जींद से खंड शिक्षा अधिकारी राजौद के रूप में हुआ है। वे 31 अगस्त 2025 तक लगभग तीन महीने अपनी सेवाएं इस पद पर देकर सेवानिवृत होंगे।

बलबीर सिंह कश्यप बहुत ही अनुभवी, मधुरभाषी, निष्ठावान, सभ्य,

बलबीर सिंह कश्यप बीआरसी कम खंड शिक्षा अधिकारी राजौंद।

कार्य में निपुण, शिक्षाविद, ईमानदार, कर्तव्य निष्ठ व्यक्तित्व के धनी इन्सान है। उनकी राजौंद खंड के सरकारी व निजी स्कूलों में अपने व्यक्तित्व की एक अमिट छाप है। वे खंड राजौंद लंबे समय तक उनकी निर्बाध, निरन्तर सेवाओं के लिए याद किए जाते रहेंगे।

बल्ला में 19 करोड़ रुपए की लागत से बिछाई जाएगी सीवरेज लाइन

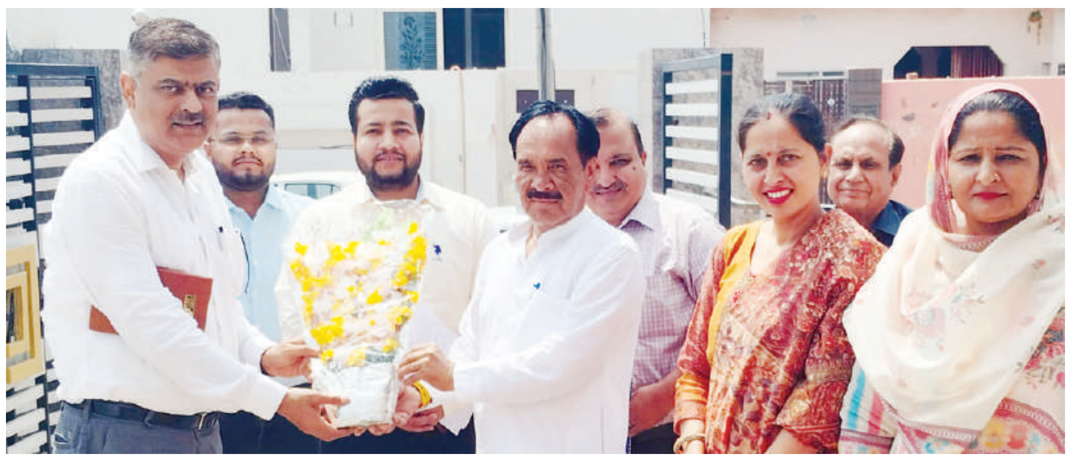

संजना भारती संवाददाता

असंध। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पंचकूला के चीफ इंजीनियर राजीव बातीश ने मंगलवार को बल्ला में बिछाई जा रही सीवरेज लाइन का निरीक्षण किया। गांव में पहुंचने पर सरपंच कर्मचंद ने उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। बाल पबाना संपर्क मार्ग पर बिछाई जा रही सीवरेज लाइन के चल रहे कार्यों का चीफ इंजीनियर ने मौके के हालात देखें। निरीक्षण के बाद उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों व ठेकेदार को निर्देश दिए की जिस गली को उखाड़ कर सीवरेज लाइन दबाई जा रही है उसे एक माह के अंदर दुरुस्त करने का कम करें ।ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा का सामान न करना पड़े।

मुख्य अभियंता ने सरपंच कर्मचंद के निवास पर ग्राम जल व सीवरेज कमेटी की बैठक में ग्रामीणों को बताया कि बल्ला में करीब 35 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन, 6.5 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन ओर तीन नए नलकूप व तीन एमएलडी एसबीआर टेक्नोलॉजी पर आधारित निर्माण कार्य सितंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पर करीब 19 करोड रुपए की लागत राशि खर्च आएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की जल कल्याणकारी योजना एवं स्वच्छ जल और मल की की व्यवस्था हर घर तक पहुंचे सके। उन्होंने बताया कि सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है कि घरेलू और औद्योगिक सीवेज के पानी को साफ कर-के उसे दोबारा उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जिला सलाहकार नेहा शर्मा ने भी ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि पानी को व्यर्थ न बहाए।

इस अवसर पर कार्यकारी अभियंता अभिषेक शेर, जिला सलाहकार नेहा शर्मा, सरपंच कर्मचंद, उप मंडल अभियंता विकास गुप्ता, बीआरसी रानी मलिक, ठेकेदार राजीव गोयल, ग्राम जल सीवरेज कमेटी के सदस्य एवं अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

तीन दिवसीय जिला टेनिस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। करनाल क्लब में आयोजित तीन दिवसीय जिला टेनिस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपने शानदार खेल कौशल और जोश से सभी का मन मोह लिया। यह प्रतियोगिता 24 मई से 26 मई तक करनाल क्लब में आयोजित की गई थी, जिसमें जिले भर से खिलाड़ियों ने भाग लिया और खेल भावना का परिचय देते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

प्रतियोगिता में करनाल के विधायक जगमोहन आनंद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। प्रतियोगिता में लड़कियों ने विशेष रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एंजल ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल, साना ने उत्कृष्ट रणनीति और तेज तर्रार खेल से गोल्ड मेडल, और आरजू मलिक ने दमदार प्रदर्शन के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इन खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण ने प्रतियोगिता को खास बना दिया। विजेताओं को नकद पुरस्कार भी दिए गए जिनमे जिनमे ब्रॉन्ज विजेता को 5000, सिल्वर विजेता को 7000 और गोल्ड विजेता को 8000 का पुरस्कार मिला। समापन के अवसर पर विजेताओं को मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उपस्थितजन ने सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में ये खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करेंगे।

करनाल क्लब के आयोजकों ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर खुशी जाहिर की और भविष्य में ऐसे और आयोजनों की रूपरेखा तैयार करने की बात कही।

नागरिक जलापूर्ति व सीवरेज के अवैध कनेक्शन को जल्द करवाएं वैध: डॉ. वैशाली शर्मा

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने सभी शहरवासियों से अपील करते कहा है कि जिन व्यक्तियों ने नगर निगम की अनुमति के बिना जलापूर्ति व सीवरेज के अवैध कनेक्शन लिए हैं, वह उन्हें जल्द से जल्द वैध करवा लें।

उन्होंने कहा कि अवैध कनेक्शन लेने वाले नागरिक निर्धारित फीस व दस्तावेज जमा करवाकर अपने कनेक्शन को वैध करवा सकते हैं। इसके लिए वह कर बिल तथा परिवार पहचान पत्र की फोटोप्रति संलग्न करके नगर निगम करनाल कार्यालय में फाईल जमा करवानी होगी। इसके साथ एक शपथ पत्र भी देना होगा।

उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक स्थानों में जिन लोगों ने नगर निगम से कनेक्शन लेकर मीटर लगवाएं हुए हैं, उनका बिल, मीटर रिडिंग के अनुसार या 1500 रुपए सालाना, जो ज्यादा हो वह आता है। इसके विपरित जिन लोगों ने मीटर नहीं लगवाएं हैं, ऐसे लोगों का सालाना बिल

सोमवार से शुक्रवार, प्रातः 9 बजे से बाद दोहपर 3 बजे तक नगर निगम कार्यालय में आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त जिन नागरिकों ने कनेक्शन लिए हुए हैं, परंतु मीटर नहीं लगवाएं हैं, वह भी अपने मीटर अवश्य लगवा लें, ताकि उनका बिल मीटर रिंडग के अनुसार भेजा जा सके।

उन्होंने कहा कि अगर किसी हाऊस होल्ड का पीने के पानी का कनेक्शन नाली व सीवर मेनहोल या निजी सीवर होदी से होकर गुजर रहा है, तो वह अपनी लाईन को बाहर से लें, ताकि पानी की मुख्य लाईन में गंदा पानी न जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता, तो उसके कनेक्शन को बिना किसी सूचना/चेतावनी के काट दिया जाएगा।

कनेक्शन के लिए यह देने होंगे दस्तावेज-उन्होंने बताया कि जलापूर्ति एवं सीवरेज कनेक्शन लेने के लिए नागरिकों को एक आवेदन लिखना होगा। आवेदन के साथ सम्पत्ति की रजिस्ट्री, मालिक का आधार कार्ड, फोटो, पडोसी का जलापूर्ति व सीवरेज बिल, सम्पत्ति 15 हजार रुपए आता है। इसके अतिरिक्त जिस मकान मालिक ने कनेक्शन लेकर मीटर लगवाया है, उसका बिल मीटर रिडिंग के अनुसार या 720 रुपये सालाना, जो ज्याद हो वह आता है। जबकि मीटर न लगने की सूरत में 1440 रुपये सालान बिल आता है। इसलिए उन्होंने कहा कि सभी लोग कनेक्शन लेने के पश्चात मीटर अवश्य लगवाएं। उन्होंने बताया कि रिहायशी बिल की दर 1 रुपये प्रति किलो लीटर तथा वाणिज्यिक बिल की दर 4 रुपये प्रति किलो लीटर है।

उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों का जलापूर्ति व सीवरेज बिल बकाया चला आ रहा है, ऐसे व्यक्तियों से भी उन्होंने अपील करते कहा है कि नगर निगम कार्यालय में अपनी बकाया राशि जमा करवा दें। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बकाया जमा नहीं करवाएगा, उसकी बिल राशि को सम्पत्ति कर बिल में जोड़ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो मकान मालिक नगर निगम कार्यालय से कनेक्शन नहीं लेगा, उसके कनेक्शन शुल्क व बिल राशि को भी सम्पत्ति कर बिल में जोड़ दिया जाएगा।

'एक सप्ताह में जिले की सभी ड्रेनों की सफाई सुनिश्चित करें सिंचाई विभाग के अधिकारी'

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। डीसी प्रीति ने कहा कि मानसून का सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए सिंचाई विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिले में जिन ड्रेनों के माध्यम से बरसात के पानी की निकासी होती है, उनके बहाव में किसी तरह की बाधा न हो। वे आगामी एक सप्ताह में साफ हो जानी चाहिए और इसकी रिपोर्ट दी जाए। ताकि उसे आला अधिकारियों को भेजा जा सके। ड्रेनों की सफाई के मामले में यदि किसी स्तर पर लापरवाही मिलती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीसी प्रीति मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ड्रेनों की सफाई कार्य की समीक्षा के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहीं थीं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश की ड्रेनों की सफाई के अब तक हुए कार्य की समीक्षा की। इस वीसी के बाद डीसी ने जिले के सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता सहित सभी कार्यकारी अभियंताओं के साथ सचिवालय के सभागार में बैठक की। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में ड्रेनों में जलखुंबी सहित अन्य बाधाओं के कारण पानी आबादी व कृषि क्षेत्र में घुसने की संभावना रहती है। जो फसल सहित जन-जीवन के लिए नुकसान का कारण बनता है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बारिश से पहले सभी ड्रेनों की सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही मानसून सीजन शुरू होने वाला है। इसलिए सरकार के आदेशानुसार जिले की संबंधित 43 ड्रेनों की साफ-सफाई एक सप्ताह में करवाना सुनिश्चित किया जाए।

ड्रेनों में जहां-जहां भी जलखुंबी व अन्य बाधाएं हैं, उन्हें हटाने का काम किया जाए। मनरेगा से, विभाग द्वारा स्वयं के संसाधनों से या फिर टेंडर के माध्यम से, जरूरत अनुसार काम का तरीका अपना कर ड्रेनों की सफाई सुनिश्चित की जाए। ताकि बारिश के समय पानी का समुचित बहाव हो सके और उसकी निकासी हो सके। उन्होंने सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ राहत के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं की जानकारी ली। साथ ही लघु, मध्यम वं दीर्घ अवधि की परियोजनाओं की जानकारी लेते हुए सभी का समय से काम पूरा करने के निर्देश जारी किए।

एसडीएम ने समारोह स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असंध। गांव सालवन में 29 मई को महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के सफल आयोजन को लेकर मंगलवार को एसडीएम असंध राहुल (आईएएस) ने समारोह स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस दौरान उनके साथ सभी उपमंडल अधिकारी उपस्थित रहे। एसडीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रम में सफल आयोजन के लिए सभी उपमंडल अधिकारियों को जो ड्यूटी निर्देशित की गई है उनका जिम्मेदारी से निर्वहन करे। एसडीएम राहुल ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के समुचित प्रबंध होने चाहिए और उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को कहा कि समारोह के दिन बिजली व्यवस्था बाधित न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने समारोह स्थल पर शौचालय की व्यवस्था तथा पर्याप्त मात्रा में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अन्य तैयारियों जिनमें सफाई, माइक एवं साउंड व्यवस्था, स्टेज के पास रंगोली, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, बेरिकेडिंग, इत्यादि के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को कहा कि समय रहते सभी आवश्यक प्रबंध किए जाए। कार्यकम में किसी भी आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

एसडीएम राहुल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी कार्यक्रम की गरिमा के अनुरूप सभी तैयारियों को समय रहते पूरा करें और कहीं पर भी लापरवाही न बरते और उचित ढंग से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें।